स्वास्थ्य बीमा योजना : एक खुली लूट

गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के नाम पर सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू की थी। इस योजना में सरकारी खर्च पर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को अधिकतम तीस हजार रुपये तक के इलाज का प्रावधान है। यह इलाज सिर्फ निजी (प्राइवेट) अस्पतालों में ही हो सकता है। निजी अस्पताल इलाज में हुए खर्च का बिल बनाकर बीमा कम्पनी को देते हैं जिसका भुगतान सरकार करती है।

ऊपर-ऊपर देखने पर लगता है कि सरकार ने यह योजना लागू करके गरीबों पर बहुत उपकार किया है। अब कोई भी गरीब इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। पहली बात, इसमें देश की कुल आबादी के सिर्फ छब्बीस फीसदी हिस्से (बीपीएल) को ही शामिल किया गया है। जबकि देश की 77 प्रतिशत आबादी 20 रुपये रोज पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी से सरकार ने गरीबों की आबादी को 26 प्रतिशत में समेट दिया है। क्या बाकी लोगों के लिये दिनों-दिन महंगे होते इलाज का खर्च उठाना सम्भव है? दूसरा, पूरे देश में दो हजार लोगों पर एक चिकित्सक है, कई राज्यों में तो पांच हजार लोगों पर एक चिकित्सक उपलब्ध है। क्या इतनी कम संख्या से गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना सम्भव है?

सरकार ने 2012-13 में इस योजना का बजट तीन सौ सात करोड़ से बढ़ाकर एक हजार पांच सौ करोड़ कर दिया। निजी अस्पताल और कम्पनियां आपस में सांठ-गांठ करके इस पैसे को हथिया रही हैं। क्या इस योजना से गरीबों का इलाज हो रहा है?

सभी जानते हैं कि गंभीर बीमारियों का इलाज तीस हजार में नहीं हो सकता। दूसरी ओर फर्जी बिल बना कर रकम वसूलने का काम भी जोरों पर है। छत्तीसगढ़ के एक अस्पताल ने छ: साल की एक लड़की का प्रसव कराने का बिल पेश किया तो झारखंड की एक निजी अस्पताल ने बीमा की रकम हड़पने के लिये गैर जरूरी रूप से रोगी की सर्जरी करा दी। बिहार के एक अस्पताल ने तो तीन महीने के एक बच्चे की आंखों में कांन्टेक्ट लेंस लगाने का रिकार्ड बनाया। स्वास्थ्य बीमा की रकम

हड़पने के लिये सबसे निंदनीय घपला महिलाओं के प्रसव के मामलों में हो रहा है। साधारण प्रसव पीड़ा में भी निजी अस्पतालों के लालची भेड़िये महिलाओं का पेट चीर देते हैं, क्योंकि इन अस्पतालों को गरीबों के इलाज की नहीं बल्कि बीमा के तीस हजार रुपये हड़पने की चिंता रहती है। इसलिये स्वास्थ्य बीमा की रकम हड़पने के लिये ये तरह-तरह के फर्जी बिल और बिना वजह ऑपरेशन कर रहे हैं।

भारतीय बीमा नियमन संस्थान के मुताबिक बीमा कम्पनियों के पास स्वास्थ्य बीमा क्षतिपूर्ति के दावों की संख्या पचास फीसदी से भी कम है। एक बड़ी बीमा कम्पनी ने इन क्षतिपूर्ति दावों की संख्या मात्र इकतीस फीसदी बतायी है। यानी सरकार ने सौ गरीबों के लिये बीमा रकम दी, लेकिन निजी अस्पतालों ने इकतीस लोगों की ओर से ही क्षतिपूर्ति का दावा किया उनमें से अधिकांशत: फर्जी थे। इस तरह बाकी का सारा पैसा बीमा कम्पनियां हजम कर गयीं।

गरीबों के इलाज के नाम पर इस सरकारी धनवर्षा को डकारने के लिये देश-विदेश की 14 बड़ी बीमा कम्पनियां मैदान में हैं। सरकार जिन गरीबों के नाम पर पैसा बहा रही है, उनको पता भी नहीं कि स्वास्थ्य बीमा योजना किस चिड़िया का नाम है। यह निजी अस्पतालों और बीमा कम्पनियों के प्रति सरकार की उदारता है। अगर सरकार को गरीबों के इलाज की जरा भी चिंता होती तो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिये सरकारी अस्पतालों का भट्टा नहीं बैठया जाता। जहां हकीकत में सभी गरीबों का सस्ता इलाज हो सकता है। उन सरकारी अस्पतालों की हालत पर भी एक नजर डाल लें जिनके बारे में पिछले दिनों अखबारों में खबर आई थी। बागपत (उत्तर प्रदेश) के सीएचसी से जाफराबाद की एक महिला को गंभीर बताकर उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। खेकड़ा पीएचसी से डॉक्टर ने नौशादा नाम की महिला को वापस भेज दिया, उसने पास के ही मोबाइल टावर के कमरे में बच्चे को जन्म दिया। बागपत सीएचसी से ही गांव शरफाबाद की सुमन को डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया था, जिसने रास्ते में दम तोड़ दिया। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान खतरा बताकर सरकारी डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं जबकि निजी अस्पतालों या घर पर उनकी नार्मल डिलीवरी हो जाती है। ऐसे भी काफी मामले हैं जब सरकारी अस्पतालों से दुत्कारी गयी गरीब महिलाओं ने सड़क किनारे या अस्पताल के अहाते में ही बच्चों को जन्म दिया।

गरीब जनता की जिंदगी बचाने के लिये गांव-गांव सरकारी अस्पताल खोलने तथा उन्हें बेहतर और उन्नत बनाने की जरूरत है। इस काम से मुंह मोड़कर सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना पर अरबों रुपये खर्च कर रही है। यह जनता के पैसे से निजी पूंजीपतियों की तिजोरी भरने वाली योजना है।

-देश विदेश

असम के दंगो की आग अब भी सुलग रही है

असम के कोकराझार और आसपास के जिलों में बोडो और मुस्लिम समुदायों के बीच जो हिंसक झड़पे हुई थीं उसकी आग अभी बुझी नहीं है। आये दिन वहां हिंसा और मौत की खबरें आती रहती हैं। तीन महीनें से भी अधिक समय बीत गया लेकिन अभी तक वहां के 80 राहत शिविरों में 36,576 मुस्लिम और 3429 बोडों परिवार अमानवीय परिस्थितियों में दिन काट रहे हैं। जुलाई-अगस्त में हुई हिंसा में उस इलाके में 97 लोगों की जान गई थी और लगभग 4 लाख 85 हजार लोग विस्थापित हुए थे। जिन लोगों के घरों को लूटा गया और उनमें आग लगाई गयी थी वे वापस लौटने पर भारी संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार ने काम चलाऊ आवास बनने के लिये प्रति परिवार 22,700 रुपये नगद, 21 टीन की चद्दरें, 6 बांस और कुछ पोलिथिन सीट पुनर्वास के लिये देना तय किया है। इतने से उन परिवारों का दुबारा बसना मुमकिन नहीं लेकिन यह बेहद मामूली सहायता भी आसानी से नहीं मिलती। दूसरे यदि वे किसी तरह रहने का ठिकाना बना भी लें, तो जीविका का कोई साधन नहीं है। दंगा प्रभावित लोगों में अधिकांश खेती से जुड़े रहे हैं। खरीफ का सीजन तो दंगे की भेंट चढ़ ही गया अब रबी की बोआई का समय भी लगता है बेकार चला जायेगा। उनके मवेशी और खेती के उपकरण दंगे की भेंट चढ़ गये हैं। सरकार की ओर से उन्हें मदद मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती। पुनर्वास के दौरान सरकार से हर परिवार को एक महीने का राशन चावल, दाल और नमक मिलना तय हुआ है। जाहिर है कि एक महिने इस अपर्याप्त भोजन पर गुजारा कर भी ले तो आगे क्या होगा? उनके लिये न तो पुंराने पेशे से जुड़ने की स्थिति है न जीविका चलाने का कोई और साधन ऐसे में लोग अपनी जमीन से उजड़ कर बाहरी इलाकों में विस्थापित होने और दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं।

भाजपा, असम गण परिषद और उनसे जुड़े संगठनों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ़ अभियान अभी जारी है। उन्होंने राहत शिविरों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों से स्थायी निवास के प्रभाव स्वरूप जमीन के पट्टों का कागज देने और इसकी जांच परख के बाद ही उनके पुनर्वास की मंजूरी देने का मुद्दा उठाया, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

यह शर्त काफी कठिन है क्योंकि अव्वल तो सबके पास जमीन का पट्टा नहीं है और है भी तो उसके कागजात दंगे में गायब हो गये हैं। किसी वैकल्पिक प्रमाण पत्र पर अभी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया है। यही कारण है कि आज कैम्पों में बोडो शरणार्थियों की तुलना में मुसलमानों की संख्या दस गुने से भी ज्यादा है। दंगे के बाद जहां शान्ति और आपसी मेल-जोल बढ़ाने की जरूरत है। साम्प्रदायिक ताकतें आज भी बोडो लोगों को मुसलमानों से कोई सम्पर्क न रखने के लिये उकसा रहे हैं और नफरत फैलाने वाली ऐसी ही दूसरी बातों का प्रयास कर रहे हैं। सच तो यह है कि आग साम्प्रदायिकता और फूटपरस्ती की राजनीति करने वालों ने ही भड़काई थी और आसानी से वे इसे बुझने नहीं देंगे।

पतित होते शिक्षक-शिष्य सम्बन्ध

आज का समय शिक्षा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जैसा कि हम जानते है कि शिक्षा का हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसा कि अनपढ़ मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा को इस बढ़ते हुए कदम को देखते हुए जगह-जगह कोचिंग क्लास खुल चूके हैं। दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है, इसे शिक्षा का मुख्य केन्द्र माना गया है। और इस दृष्टि से दिल्ली में भी कोचिंग क्लासेस की कोई कमी नहीं है। पर क्या इनमें से 70 प्रतिशत कोचिंग क्लास भी सही मायने में है? क्या ये विद्यार्थियों का सिर्फ शोषण नहीं कर रहे? ये उनकी परेशानी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आजकल स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को संतुष्ट करने वाली पढ़ाई नहीं हो पाती है, बल्कि यहां पढ़ाई के नाम पर बहुत कुछ हो जाता है। कहा गया है कि विद्यालय की तुलना एक मंदिर से की गई है, और शिक्षको को देवता से। हमारे शास्त्र में गुरू का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। कबीरदास जी ने लिखा है।

गुरू गोविंद दोऊ खड़े हैं काके लागु पांव।
बलिहारी गुरू आपको जिन्हों गोविंद दियो बताय।

भगवान और गुरू दोनों खड़े हैं तो गुरू को इसलिये पहले पैर छुना है कि गुरू ने ही बताया है कि यह भगवान है। पर आजकल शिक्षकों और छात्र-छात्राओं की छवि बदल गई है। सिर्फ बात यहां तक नहीं, बहुत आगे बढ़ चुका है। आपस में लडके लड़कियां भी ब्वॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड बनाने जाते हैं। आश्चर्य की बात तो तब होती है जब यह सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रह कर शिक्षक तक भी हो जाता है। कितने लड़के-लड़कियां के प्रेम-प्रसंग शिक्षक और शिक्षिकाओं से भी होते हैं।

स्कूल में तो कोर्स पूरा हो नहीं पाता है तो बच्चों को कोचिंग का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। और कोचिंग के काऊंसलर शिक्षक तो बस इसकी राह देखते रहते हैं। कितने स्कूलों में तो स्कुल की तरफ से ही कोचिंग की व्यवस्था होती है। इसका मतलब तो यह है कि वो बच्चों को कोर्स विद्यालय में सही ढ़ग से पूरा

जब शिक्षिका को इस बात का पता चला तो वह कुछ नहीं बोली और अपनी फेस बुक से उस छात्र का नाम हटा दिया। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश कितना विकास कर पायेगा। शिक्षक छात्र के भविष्य और उनके अभिभावक के पैसों से खेलते रहे तो क्या होगा। क्या हमारे देश की संस्कृति धूमिल होने से बच पायेगी।

कराना ही नहीं चाहाते। इसलिये कि कोचिंग में अलग से मुनाफा कमा सके यह तो शिक्षा का व्यापार है।

पर कोचिंग की स्थिति तो और बद से बदतर है। वहां पहले कोर्स के अनुसार पूरी फीस रखवा ली जाती है और इसके बाद पढ़ाई के नाम पर बच्चों से गपशप और उनका मजाक बनाकर टाइम पाश किया जाता है। एक छोटे से ट्यूशन सेंटर की बात है वहां सातवीं क्लास के एक लड़के ने अपनी शिक्षिका को आई लव यू कहा तो शिक्षिका ने इसके विपरित कोई कदम नहीं उठाया, फिर बाद में प्रस्ताव स्वीकार कर उसके साथ डेट पर भी गई। जब छोटे कोचिंग का यह हाल है, तो सोचने की बात है कि बड़े-बड़े संस्थानों कां क्या हाल होगा।

एक इंस्टच्यूट में एक शिक्षक ने वहां पढ़ रही एक छात्रा को प्रपोज किया। छात्रा ने शिक्षक को नीति और धर्म का उपदेश दी। इस पर शिक्षक ने ब्यंग्य किया, कि यह द्रोणाचार्य की शिष्या है पता नहीं कौन सी सदी से गुजर रही है। इस बात को सुनते हुए वहां जितने भी छात्र-छात्रा थे सभी को मजाक उड़ाने का मौका मिल गया और कुछ शिक्षक और छात्राओं से चर्चित कहानी ले कर बोलने लगा। जैसे मटुक नाथ चौधरी और जुली की बात ले आया। जहां शिक्षकों के इस कदर नीच विचार हों, वहां पर कोई सीधी-सादी छात्रा कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर पायेगी। उसके लिये तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। छात्रा पूरी फीस देकर वहां कोर्स पूरा करने गई थी, उसे बीच में ही छोड़कर अलग कोर्स पूरा करना पड़ा। एपटेक नामक संस्थानं की एक शिक्षिका ने बी सी ए के एक छात्र की नाजूक हालत को देखते हुए वह उसे अपने घर पर बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। साथ-साथ उस छात्र को अपनी जी मेल आई डी तथा फेस बुक से भी ऐड कर लिया। और जब भी कभी उस छात्र को पढ़ाई के दौरान कुछ परेशानी होती तो वो ऑनलाइन भी शिक्षिका से सवाल करता और वह शिक्षिका सवाल का जवाब देती थी। शिक्षिका का नजरिया गोई गलत नहीं था, वो उस छात्र के सारे पेपर की तैयारियां करवा देना चाहती थी। पर उस छात्र ने गलत नजरिये से देखा और अपने दोस्तों के बीच यह बात फैला दिया कि मैडम मुझे पसंद करती है इसलिये मुझ पर इतना ज़्यादा ध्यान देती है। जब शिक्षिका को इस बात का पता चला तो वह कुछ नहीं बोली और अपनी फेस बुक से उस छात्र का नाम हटा दिया। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश कितना विकास कर पायेगा। शिक्षक छात्र के भविष्य और उनके अभिभावक के पैसों से खेलते रहे तो क्या होगा। क्या हमारे देश की संस्कृति धूमिल होने से बच पायेगी।

-अर्पिता झा